क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निहित भूमि और कब्जे में ली गई भूमि	व्यक्तिगत लाभार्थियों में वितरणा	प्रतिशत
9.	केरल	95984	64765	67.47
10.	मध्य प्रदेश	306150	185624	60.63
11.	महाराष्ट्र	666190	556532	83.54
12.	मणिपुर	1685	1685	99.82
13.	उड़ीसा	166150	155193	03.41
14.	पंजाब	105181	103545	98.44
15.	राजस्थान	567010	458734	80.90
16.	तमिलनाडु	171114	165922	96.96
17.	त्रिपुरा	1944	1599	82.25
18.	उत्तर प्रदेश	537112	400843	74.63
19.	पश्चिम बंगाल	1261859	1023663	81.14
20.	दादर व नगर हवेली	9305	6851	73.63
21.	दिल्ली	394	394	100.00
22.	पांडिचेरी	1160	1023	88.10
	कुल	6624992	5285501	79.78

परिधान क्षेत्र का आधुनिकीकरण

916. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिधान क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा उसके आधुनिकीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या बजटीय प्रावधान किए गए हैं;और

(घ) क्या परिधान क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की कोई कार्य योजना हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) सरकार ने प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना को शुरू करने का अनुमोदन किया है जिसके अतंर्गत पात्र वस्त्र और पटसन एककों को ब्याज की लागू दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा । इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों/बैकों से पात्र एककों को 5% का ब्याज प्रोत्याहन दिया जाएगा । इस योजना के अंतर्गत परिधान क्षेत्र को भी शामिल किया गया है । तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड़वी) परिधान क्षेत्र को ऋण दात्री नोडिए एजेंसी होगी । यह योजना 1.4.1999 से शुरू की जाएगी ।

इसके अतिरिक्त सरकार निर्यातोन्मुख परिधान क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर कदम उठा रही है जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकों,मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना,निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करने का अधिकार देना,निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना,निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना,मानव संसाधन विकास तथा समूचे देश में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करना आदि ।

Bar by oEC on Indian testils exports

917. SHRI SANTHOSH BAGRODIA:

Will the Minsite of TEXTILES be pleased to state

(a) whether it is a fact that European Commission has barred expotrs of garments and trousers from Indiaworth hundreds of crores for no crores for no ;serious resason: and